Tribe Students and also book bank schemes. These are the schemes under which the programme is implemented.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Sir, the Minister has said that 10 lakh families have benefited. It is indeed spectacular. He deserves congratulations on that. But then, I want one clarification from him. If 10 lakh families have benefited in Rs. 39 crores, how much benefit has each family got? It will come to a couple of hundred rupees. Out of Rs. 39 crores, 10 lakh families have benefited! What is the actual benefit per family? I am not clear as to what sort of actual benefits have gone to the families. There may be some general types of schemes under which each family may not have got individual benefits, but must have got general benefits. I would like the Minister to clarify more on this aspect.

Now, should I put the second supplementary, Sir?

MR. CHAIRMAN: You have already put it.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Sir, that was a clarification sought on the reply to the first supplementary. I would like to put my second supplementary.

MR. CHAIRMAN: All right.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: My second supplementary is this, Sir. As per the (c) part of the reply, the State of Bihar was No. 2 in taking the benefits of these schemes. In 1993-94. Bihar went to the No. 3 position. And in 1994-95, Bihar is not among the first five. What is the reason? Why has Bihar not utilised this money? Why did Bihar, which was No. 2, in 1992-93, became No. 3 in 1993-94 and is not at all there among the first five in 1994-95 whereas Maharashtra is going up? What is the reason for this?

SHRI K.V. THANGKA BALU: Sir, every year, the State Governments are submitting proposals to the Central Government. On the basis of the recommendations made by the State Governments, we release monies to the State Governments for various schemes as I mentioned before. Even this year, Maharashtra has got only Rs. 36 crores whereas last time, we released Rs. 39 crores, because they have not submitted their proposals accordingly. As and when they submit their proposals, we do recommend the money to be sent immediately.

With regard to Bihar, in fact, the Bihar Government did not submit the proposals in time. Also, whatever money we have sent them, they have not utilised also. Even the 'utilised' certificate has not come to us. That is why even last time, we stopped the grant to the Bihar Government.

MR. CHAIRMAN: One clarification is required about the number of families benefited. How much money has a family actually got?

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Rs. 39 crores for about 10 lakh families. I want a clarification on that.

SHRI K.V. THANGKA BALU: The proposals were sent by the State Governments. The ITDP consists of area development. The number of families they select in the areas is the criterion. As per the State Government's recommendations, we sanction money to the State. It is for the State Government to see that the money is disbursed for the development and welfare of Scheduled Tribe families. Accordingly, they submit figures. I have mentioned the figures given by the Maharashtra Government.

Target for Production of Rabi Food-grains

*125. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the target fixed by Government for production of Rabi foodgrains in the country during the year 1995-96;

(b) the target fixed by Government for the State of Punjab in this regard; and

(c) the concrete steps Government propose to take to achieve the targets of foodgrains production in Punjab?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The target fixed for the production of Rabi foodgrains in the country during the year 1995-96 is 84.50 million tonnes.

(b) The target fixed for the State of Punjab for Rabi foodgrains during 1995-96 is 12.73 million tonnes.

(c) For increasing the production and productivity of foodgrains in the State of Punjab, the following measures are being taken through Integrated Cereals Development Programme in Wheat Based Cropping System.

(i) to propogate newly released high yielding varieties and replace the disease susceptible old varieties;

(ii) to improve the resource base of the farmers for timely field operations and sowing including incentives for implements and sprinkler irrigation sets;

(iii) transfer of technology through frontline and general demonstrations;

(iv) propogation of integrated pest management.

In addition, price and market support is also being provided.

श्री इकबाल सिंह: चैयरमेन सर, आदरणीय मंत्रीजी ने प्रश्न के भाग ''क'' और ''ख'' का जवाब दिया है, जिस में उन्होंने पंजाब राज्य में खाद्यानों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गेहूं आधारित फसल प्रणाली में एकीकृत विकास कार्यक्रम के माध्यम से कुछ उपाय बताए हैं, लेकिन मैं यहां मंत्री जी से ''डिफर'' करता हूं और चाहता हूं कि इस विषय में दोबारा उत्तर आना चाहिए। अभी अपनी सप्लीमैंटरी में मैं यह कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स की कीमतों में वृद्धि होने से पंजाब के किसानों को न तो कोई लाभ प्राप्त हो रहा है और न ही उन्हें अपनी कृषि उपज का उचित मूल्य ही मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आप को बताना चाहता हूं कि 1992 में यूरिया के दाम 115 रुपए प्रति बैग थे और 1995 मे इस का रेट बढ़कर 160 रुपए प्रति बैग हो गया है। इसी तरह 1992 में डी॰ए॰पी॰ का दाम 270 रुपए प्रति बैग था, यह 1995 में बढ़कर 485 रूपए प्रति बैग हो गया। इसी तरह पोटाश, बिजली आदि के बिल और आयरन रॉड जोकि किसान के काम में आते हैं, उन के रेट बहुत बढ़ गए हैं। मंत्रीजी ने उत्तर में यह भी दिया है कि इसके अतिरिक्त मूल्य और मण्डी समर्थन की व्यवस्था भी है। चैयरमेन सर, मैं आदरणीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इनपुट्स के रेट्स इतने बढ़े हैं, क्या किसान इनके द्वारा फिक्स्ड रेट का मुकाबला कर सकेगा? आज जो ट्रेडर है, वह जो चीज इंडस्ट्री में बनाता है, उस का रेट वह आप फिक्स करता है। लेकिन भारत के किसान को रेट फिक्स करने की छूट नहीं दी गयी है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आज के दिन पंजाब के किसान ने इतनी मेहनत कर जो इतना अनाज सैंटर पूल में दिया है, उसे अच्छे रेट प्राप्त हों इसके लिए मंत्रीजी क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री मोहम्मद अयूब खान: गोहतरम् चैयरमेन साहब, पंजाब के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हम ने खरीफ में 107.50 मिलियन टन बनाया, रबी में 84.50 मिलियन टन बनाया और हमारा कुल उत्पादन 192 मिलियन टन है। पंजाब हमारे देश का वह प्रांत है जोकि फूड-ग्रेन उत्पादन में सब से आगे है। पंजाब का लक्ष्य 7.7 मिलियन टन खरीफ का है और 12.7 रबी का है। इस तरह पंजाब टोटल 25 मिलियन टन प्रोडक्शन कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संबंध में तो किसानों की तरक्की के लिए हम ने जो बातें बतायी है पंजाब के संबंध में और तमाम के संबंध में, वह इस तरह से है....

श्री एस.एस. सुरजेवाला: वह जवाब में दे रखा है, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए।

श्री मोहम्मद अयूब खान: सपोर्ट प्राइस का अध्ययन हमारी कमेटी करती है और उस के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह तय करती है। यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ही बदौलत है कि हमारा फूड-ग्रेन बढ़ा है जिस में पंजाब भी शामिल है। सन् 1950 के अंदर और आज वर्ष 1995-96 को हम देखें तो आज हमारा मुल्क 192 मिलियन टन अनाज पैदा करता है। यह कोई मामूली बात नहीं है और यह इन मूल्यों के ही बदौलत, नयी जानकारी के बदौलत और हमारे मुल्क के साईंटिस्ट्स की बदौलत है कि आज हमारा मुल्क 192 मिलियन टन अनाज पैदा करता है। उस में पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसा मेरा मानना है।

श्री इकबाल सिंह: सर, मैं सेकेण्ड सप्लीमेंटरी करने से पहले अपने पहले क्वेश्चन का उत्तर जरूर चाहता हूं। आप मुझे प्रोटेक्ट करिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, मैंने अभी जैसी फिगर दी है कि 1991 में क्या रेट या यूरिया था और 1995 में आज क्या रेट है, तो मैं यह चाहता हूं, आप देखिए जो इंडस्ट्रलिस्ट हैं, कोई चप्पल बनाता है, कोई स्पोर्ट का सामान बनाता है, कोई हैंडटूल्स बनाता है तो वह रेट फिक्स करता है अपना, जो

उसका लगा हुआ पैसा है, उसके मुताबिक, लेकिन माननीय मंत्री जी, यह इतने रेट बढ़ गए हैं 1991 से 1996 तक । .....(व्यवधान).....

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा॰ जगन्नाथ मिश्र): सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य को मालूम है कि खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण करने के लिए जो हमारी मूल्य आयोग गठित है, वह विस्तार से समीक्षा करती है उत्पादन मूल्यों का और उसी हिसाब से सपोर्ट प्राइस की घोषणा सरकार करती है उनकी अनुशंसा पर। आंकड़े बताते हैं कि जो इनपुट्स के मूल्य बढ़े हैं, उस हिसाब से उत्पादन मूल्य भी बढ़े हैं और उसकी सूचना ली है इस आयोग में । वर्ष 1991-1992 में जहां गेंहू का उत्पादन मूल्य 168/- रुपए क्विंटल माना गया था, वहां आज 310/- रुपए प्रति क्विंटल माना गया है इस समय। प्रत्येक साल का अगर देखें तो 1991-92 में 168/- रुपए था, 1992-93 में 250/-, 1993-94 में 281/- 1994-95 में 236/- और 1995-96 में 310/- रुपए । अब यह आयोग तो विचार करती ही है। जो मूल्य बढ़ोतरी है इनपुट्स पर, उस पर विचार करने के उपरांत वह अनुशंसा करती है कि सरकार को सपोर्ट मूल्य क्या करना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य की यह धारणा कि जो यूरिया के या दूसरे पदार्थों के मूल्य बढ़ रहे हैं सरकार उसका ध्यान नहीं रखती, सही नहीं है। सभी बिन्दुओं, पर मूल्य आयोग विचार करते हुए अनुशंसा करती है।

MR. CHAIRMAN: Please put your second supplementary.

श्री इकबाल सिंह: चैयरमेन साहब, सेकेण्ड सप्लीमेंटरी में पूछता हूं, लेकिन यह रेसो के मुताबिक मूल्य नहीं बढ़े हैं, पंजाब के किसान को मूल्य नहीं मिल रहे। मेरी सेकेण्ड सप्लीमेंटरी यह है कि पंजाब राज्य, जो कि बहुत साल टेरारिज्म में फंसा रहा और पंजाब का किसान, जिसकी इन्होंने बहुत अभी प्रशंसा की है, पंजाब के किसान ने बहुत काम किया है एग्रीकल्चर में। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने लाखों टन चावल वहां पड़ा हुआ है और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी 1994 में, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर ने जो उस समय फैसला लिया था कि जो 35 परसेंट बढ़ोतन चावल है उसको यह फाइन और सुपर फाइन आधार देकर के पंजाब से चावल लेंगे, लेकिन आज 96 हो गया, पंजाब का चावल वहीं पड़ा हुआ है। पंजाब का किसान इसके लिए बहुत दुखी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कोई जल्दी से जल्दी ऐसी रिपोर्ट तैयार की है, जिससे किसान को फायदा हो सके और पंजाब का जो चावल गोदामों में पड़ा हुआ है और बाहर पड़ा हुआ है, उसको यह उठा सकें सेंट्रल पूल के लिए?

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: सरकार के ध्यान में सभी राज्यों की समस्याएं आती हैं। यह संभव नहीं हो सकता कि सभी राज्यों की सविस्तार जानकारी सरकार के पास हो। जिन राज्यों की विशेष समस्या हैं, उस पर सरकार ध्यान देती है और किसानों को उत्पादन का मूल्य मिले खुले बाजार में, अगर खुले बाजार में मूल्य नहीं प्राप्त होता है या खाद्यान्न की बिकी नहीं होती है तो सरकार की तरफ से उनके खाद्यान्न खरीदे जाते हैं।

श्री इकबाल सिंह: सर, यह मैंने मूल्य की बात नहीं की, मैंने चावल उठाने की बात की है। सारी इंडस्ट्री फेल हो चुकी है एग्रो इंडस्ट्रीज, राइस शैलर सारे बंद हो चुके हैं।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: अब यह सूचना तो इस समय विस्तार से नहीं है। माननीय सदस्य की जानकारी करा देंगे।

श्री एस. एस. सुरजेवाला: चैयरमेन सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गेंहू की फसल में मंडूसी नाम का एक वीड है, जिसकी शक्ल बिल्कुल गेंहू के साथ मिलती जुलती है और सच तो यह है कि मंडूसी वीड जो है, उसने पूरे गेंहू का जो प्रोडक्शन है, पैदावार है उसको 25 से लेकर 50 प्रतिशत कम कर दिया है, तो आपके मंत्रालय ने इस बारे में क्या उपाय किए हैं ताकि किसान की रक्षा की जा सके और यह मंडूसी जो वीड है वह नष्ट हो सके? क्योंकि कितने ही स्प्रे करवाएं, सारे स्प्रे के बावजूद भी मंडूसी जो है वह गेंहू के ऊपर से जाती नहीं है। दूसरा, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा ....(व्यवधान)....

श्री सतीश अग्रवाल: एक का जवाब तो आने दें।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: जो हमारे अनुसंधान केन्द्र भिन्न-भिन्न राज्यों में, उन अनुसंधान केन्द्रों में जो जानकारी प्राप्त होती है, उस हिसाब से हम किसानों को हिदायत जारी करते है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, अनुसंधान के मामले में इसे प्रस्तुत कर देंगे।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट

*122. श्री सुन्दर सिंह भंडारी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: